

द मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड, कलकत्ता

बनाम

भारत संघ एवं एक अन्य

31 अगस्त, 1960

(बी. पी. सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, जे. एल. कपूर, पी. बी. गजेंद्रगडकर, के. सुब्बा राव एवं
के. एन. वांचू, न्यायमूर्तिगण)

खनन पट्टा—क्या इसमें उप-पट्टा शामिल है—खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53), धारा 3(डी)—खनिज रियायत नियमावली, 1949।

अपीलकर्ता, जो एक लिमिटेड कंपनी है और एक खनन पट्टे की पट्टादार थी, ने अपने अनुदान में शामिल दो गाँवों के संबंध में एक उप-पट्टा दिया। कंपनी के सचिव और दो निदेशकों पर खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि, पहली बात यह कि उप-पट्टा अधिनियम की "खनन पट्टा" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, और इस प्रकार अधिनियम और नियम उप-पट्टे पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं; और दूसरी बात यह कि, चूंकि ये नियम अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए थे न कि धारा 7 के तहत, इसलिए वे किसी पट्टादाता द्वारा दिए गए उप-पट्टे पर लागू नहीं होते हैं, भले ही वह उप-पट्टा अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया हो, यदि पट्टादाता का स्वयं का पट्टा अधिनियम और नियमों के लागू होने की तारीख से पहले का था।

अभिनिर्धारित किया गया कि खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3(डी) में निहित "खनन पट्टा" की परिभाषा के लिए यह आवश्यक नहीं है

कि पट्टादाता अनिवार्य रूप से एक स्वामी ही हो। इसकी स्पष्ट भाषा को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 5 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि खनन पट्टे में वह पट्टा भी शामिल है जो किसी स्वामी द्वारा निष्पादित किया गया हो और वह पट्टा भी जो ऐसे स्वामी से पट्टा प्राप्त करने वाले पट्टादार द्वारा निष्पादित किया गया हो। यह तथ्य कि पट्टादाता स्वयं एक पट्टादार है, और उसके तथा उस व्यक्ति (जिसके पक्ष में वह पट्टे के माध्यम से अंतरण करता है) के बीच के लेनदेन को उप-पट्टा कहा जाता है, उनके बीच होने वाले अंतरण की प्रकृति को किसी भी तरह से नहीं बदलता है।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियम किसी खनन उप-पट्टे पर तब लागू होंगे, यदि वह अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया हो।

दीवानी अपील की क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 231/1955।

स्वत्व वाद संख्या 105/1953 में पटना उच्च न्यायालय के 16 फरवरी, 1954 के निर्णय और डिक्री से अपील।

एन. सी. चटर्जी, संजीव चौधरी और गणपत राय, अपीलकर्ता की ओर से।

सी. के. दफ्तरी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, पी. के. चटर्जी और टी. एम. सेन, उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से।

लाल नारायण सिन्हा, बजरंग सहाय और आर. सी. प्रसाद, उत्तरदाता संख्या 2 की ओर से।

31 अगस्त, 1960। न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वांचू द्वारा सुनाया गया।

न्यायमूर्ति वांचू- यह पटना उच्च न्यायालय की एक डिक्री के विरुद्ध अपील है। अपीलकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है। रामगढ़ के राजा द्वारा 29 दिसंबर, 1947 को रामगढ़ रियासत के भीतर स्थित 3026 गांवों के संबंध में 999 वर्षों की अवधि के लिए अपीलकर्ता को एक खनन पट्टा प्रदान किया गया था

और अपीलकर्ता को उसका कब्जा सौंप दिया गया था। 1 फरवरी, 1950 को अपीलकर्ता ने अपने अनुदान में शामिल दो गांवों का 15 वर्ष की अवधि के लिए भगत सिंह नामक व्यक्ति को एक उप-पट्टा प्रदान किया। इसी बीच, उस क्षेत्र में जहाँ वे दो गाँव स्थित थे, खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (1948 का अधिनियम संख्या LIII) (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और खनिज रियायत नियमावली, 1949 (जिसे इसके बाद नियमावली कहा गया है) लागू हो चुके थे। तत्पश्चात, भगत सिंह ने नियमावली के तहत अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए उपायुक्त, हजारीबाग के पास आवेदन किया। इस पर, उपायुक्त ने यह विचार करते हुए कि दिया गया उप-पट्टा अधिनियम और नियमावली के उल्लंघन में था, 25 सितंबर, 1951 को एक दंडाधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता के दो निदेशकों और सचिव के विरुद्ध शिकायत दर्ज की, जिसमें उन पर नियमावली के नियम 45, तथा नियम 47 और 49 (अब नियम 51) को नियम 51 (अब नियम 53) और अधिनियम की धारा 9 के साथ पढ़ते हुए, उनके उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जब आपराधिक मामला चल रहा था, तब अपीलकर्ता ने अधिनियम और नियमावली की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक वाद दायर किया। इस चुनौती के समर्थन में कई आधार लिए गए थे, लेकिन अब उन सभी को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क केवल दो बिंदुओं तक सीमित रखे हैं, अर्थात्: (i) उप-पट्टा अधिनियम की धारा 3(डी) में 'खनन पट्टा' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए अधिनियम और नियमावली उप-पट्टे पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं, और (ii) चूंकि ये नियम अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए थे न कि धारा 7 के तहत, इसलिए वे किसी पट्टादाता द्वारा दिए गए उप-पट्टे पर लागू नहीं होते हैं, भले ही वह उप-पट्टा अधिनियम और नियमावली के लागू होने के बाद दिया गया हो, यदि पट्टादाता का स्वयं का पट्टा अधिनियम और नियमावली के लागू होने की तारीख से पहले का था।

उत्तरदाताओं द्वारा वाद का विरोध किया गया और उनका बचाव यह था कि 'खनन पट्टा' शब्द में उप-पट्टा शामिल है और अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियम उन सभी उप-पट्टों पर लागू थे जो अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिए गए थे।

उच्च न्यायालय ने अधिनियम और नियमों की वैधता और संवैधानिकता के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 3(डी) में यथा परिभाषित 'खनन पट्टा' शब्द में उप-पट्टा शामिल है, और इसलिए अधिनियम और नियम उन उप-पट्टों पर लागू होते हैं जो अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिए गए हैं; और यह तथ्य अप्रासंगिक था कि अपीलकर्ता को प्रदान किया गया पट्टा अधिनियम और नियमों के लागू होने के समय से पूर्ववर्ती था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर, वाद को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने एक प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार यह मामला हमारे समक्ष आया है।

बिंदु (I) क संबंध में

विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 3(डी) में यथा परिभाषित 'खनन पट्टा' शब्द में उप-पट्टा शामिल है। धारा 3 का खंड (डी) इन शब्दों में है :-

"'खनन पट्टा' का अर्थ खनिज की खोज करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने, उन्हें निकालने, उन्हें व्यापार योग्य बनाने, उन्हें ले जाने, या उनके निपटान के उद्देश्य से, या उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए दिया गया पट्टा है, और इसमें अन्वेषण या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति शामिल है;"।

इसमें उप-पट्टे का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन यदि धारा 3(डी) में प्रयुक्त शब्दों के सामान्य अर्थ को लिया जाए, तो यह स्पष्ट है कि 'खनन पट्टा' शब्द का अर्थ खनिजों की खोज करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने, उन्हें निकालने, उन्हें व्यापार योग्य बनाने,

उन्हें ले जाने या उनके निपटान के उद्देश्य से, या उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए दिया गया किसी भी प्रकार का पट्टा है। यह महत्वपूर्ण है कि परिभाषा में यह आवश्यक नहीं है कि पट्टादाता अनिवार्य रूप से स्वामी ही हो; और इसलिए इसकी उचित व्याख्या करने पर इसमें वह पट्टा भी शामिल होगा जो स्वामी द्वारा निष्पादित किया गया हो और वह पट्टा भी जो ऐसे स्वामी से पट्टा प्राप्त करने वाले पट्टादार द्वारा निष्पादित किया गया हो। यदि हम संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में 'पट्टे' की परिभाषा को देखें, तो हम पाते हैं कि अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का एक अंतरण है, जो एक निश्चित समय के लिए, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, या शाश्वत काल के लिए, भुगतान की गई या भुगतान करने का वचन दी गई कीमत के प्रतिफल के रूप में, या धन, फसलों के हिस्से, सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के बदले में किया जाता है, जिसे अंतरिती द्वारा अंतरणकर्ता को समय-समय पर या निर्दिष्ट अवसरों पर दिया जाना होता है, और अंतरिती ऐसे निबंधनों पर अंतरण स्वीकार करता है। इसलिए, एक पट्टे के लिए जो आवश्यक है वह है—एक अंतरणकर्ता, एक अंतरिती और धारा 105 में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अचल संपत्ति का अंतरण। पट्टा देने के लिए अंतरणकर्ता को अपना अधिकार कैसे प्राप्त होता है, यह तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि लेनदेन धारा 105 में परिभाषित प्रकृति का है। अतः अधिनियम की धारा 3(डी) के स्पष्ट शब्दों और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में निहित पट्टे की परिभाषा को लागू करते हुए, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि इस मामले में एक अंतरणकर्ता (अर्थात् अपीलकर्ता) और एक अंतरिती (अर्थात् भगत सिंह) है जिसने अंतरण स्वीकार किया है; यह लेनदेन अचल संपत्ति के संबंध में है और इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, एक निश्चित अवधि के लिए और प्रतिफल के बदले ऐसी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार सृजित करता है। अतः, यद्यपि इस तथ्य को देखते हुए कि अंतरणकर्ता अंतरित संपत्ति का स्वामी नहीं है बल्कि स्वयं एक पट्टादार है, दस्तावेज़ को उप-पट्टा कहा जा सकता है, फिर भी अपीलकर्ता और भगत सिंह के बीच का यह लेनदेन

एक खनन पट्टे के अलावा और कुछ नहीं है। 'उप-पट्टा', 'अधो-पट्टा' और 'व्युत्पन्न पट्टा' जैसे शब्दों का प्रयोग सुविधा के लिए न केवल यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि वह अंतरण एक पट्टा है, बल्कि यह भी कि अंतरणकर्ता संपत्ति का स्वामी नहीं है बल्कि स्वयं एक पट्टादार है; लेकिन एक पट्टादार और उप-पट्टादार के बीच का अंतरण फिर भी एक पट्टा ही है, बशर्ते कि वह धारा 105 की परिभाषा को पूरा करता हो। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय V, जो अचल संपत्ति के पट्टों से संबंधित है, ने कहीं भी पट्टे और उप-पट्टे के बीच कोई अंतर नहीं किया है और उस अध्याय के सभी प्रावधान जो पट्टे पर लागू होते हैं, वे उप-पट्टे पर भी लागू होते हैं। केवल पट्टादार के अधिकारों और दायित्वों पर विचार करते समय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 108(जे) यह निर्धारित करती है कि पट्टादार संपत्ति में अपने पूरे या किसी भी हिस्से के हित को पूर्ण रूप से, या बंधक अथवा उप-पट्टे के माध्यम से अंतरित कर सकता है, और यहीं पर उप-पट्टे का उल्लेख मिलता है, अर्थात् यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया पट्टा है जो स्वयं एक पट्टादार है। लेकिन यह तथ्य कि पट्टादाता स्वयं एक पट्टादार है और उसके तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में वह पट्टे के माध्यम से अंतरण करता है के बीच के लेनदेन को उप-पट्टा कहा जाता है, उनके बीच होने वाले अंतरण की प्रकृति को किसी भी तरह से नहीं बदलता है। इसलिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 3(डी) के स्पष्ट शब्दों के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 'खनन पट्टा' शब्द में उप-पट्टा शामिल है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में कई कानूनों का संदर्भ दिया जहाँ 'पट्टा' शब्द में स्पष्ट रूप से उप-पट्टा को शामिल बताया गया है। खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का LXVIII), जिसने इस अधिनियम (1948 के अधिनियम) का स्थान लिया है, में 'खनन पट्टा' को धारा 3(सी) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है खनन कार्यों को करने के उद्देश्य से दिया गया पट्टा और इसमें उप-

पट्टा शामिल है। 1957 का अधिनियम इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बनाया गया था और विधायिका ने संभवतः *अत्यधिक सावधानी के तौर पर* यह कहना उचित समझा कि 'खनन पट्टा' शब्द के भीतर उप-पट्टा शामिल है। संबंधित अंग्रेजी अधिनियम और साथ ही अंग्रेजी संपत्ति कानून, 1925 में भी पट्टे की परिभाषा में उप-पट्टे को शामिल किया गया है। हालांकि, यह तथ्य कि कुछ कानूनों में पट्टे को उप-पट्टे सहित परिभाषित किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि पट्टे में अन्यथा उप-पट्टा शामिल नहीं हो सकता। इसके विपरीत एक उदाहरण संपत्ति अंतरण अधिनियम है, जहाँ 'पट्टा' शब्द की परिभाषा में स्पष्ट रूप से उप-पट्टा शामिल है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ ऐसे निर्णयों पर भी भरोसा किया जिनमें यह निर्धारित किया गया था कि पट्टे में उप-पट्टा शामिल नहीं था। हालांकि, वे निर्णय उस समय विचाराधीन अधिनियम की विशिष्ट शर्तों पर आधारित थे, और इस प्रश्न का निर्धारण करने में सहायक नहीं हैं कि क्या इस अधिनियम में 'खनन पट्टा' शब्द में खनन उप-पट्टा शामिल है। सामान्यतः, एक पट्टे में उप-पट्टा तब तक शामिल माना जाएगा जब तक कि उस विशेष कानून में इसके विपरीत कुछ न हो। हम इस संबंध में *कैम्बरवेल एंड साउथ लंदन बिल्डिंग सोसाइटी बनाम होलोवे* मामले में जेसल, एम. आर. द्वारा पृष्ठ 759 पर दी गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं :-

"कानून में 'पट्टा' शब्द एक सुविख्यात कानूनी शब्द है जिसका अर्थ भली-भांति परिभाषित है। किसी भी अधिवक्ता ने कभी यह सुझाव नहीं दिया है कि पट्टादाता के स्वत्व से दस्तावेज के विवरण में कोई अंतर आता है, चाहे पट्टा किसी पूर्ण स्वामित्व धारक द्वारा दिया गया हो या किसी लॉर्ड की अनुज्ञप्ति के साथ कॉपीहोल्डर द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो स्वयं एक पट्टाधारक हो। चूंकि इसे वर्षों की एक अवधि के लिए वैध रूप से प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे पट्टा कहा जाता है। यह बिल्कुल सच है कि जहाँ पट्टा देने

वाला व्यक्ति स्वयं एक निश्चित अवधि के लिए हक रखता है, वहाँ दूसरे दस्तावेज़ को अधो-पट्टा या व्युत्पन्न पट्टा कहा जाता है, लेकिन वह फिर भी एक पट्टा ही होता है.....।"

हमें अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो यह संकेत दे कि धारा 3(डी) में परिभाषित 'खनन पट्टा' शब्द में खनन उप-पट्टा शामिल नहीं है। इसके विपरीत, जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ यह अधिनियम पारित किया गया था, उसे देखते हुए हमें यह पूरी तरह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'खनन पट्टा' शब्द के अंतर्गत उप-पट्टा शामिल होना ही चाहिए, जैसा कि यह स्पष्ट रूप से धारा 3(सी) के सरल शब्दों के दायरे में आता है।

यह तथ्य कि अधिनियम खानों और तेल क्षेत्रों के विनियमन और खनिजों के विकास का प्रावधान करता है, यह दर्शाता है कि इसे जनहित में पारित किया गया था। मंशा यह थी कि देश की खनिज संपदा को संरक्षित किया जाना चाहिए और उसका बिना किसी बर्बादी के उचित तरीके से, तथा उस कार्य में योग्य व्यक्तियों द्वारा दोहन किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 5 अन्य बातों के साथ-साथ उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने का प्रावधान करती है जिन पर खनन पट्टे दिए जा सकते हैं, तथा वह अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र और वह अवधि जिसके लिए ऐसे पट्टे दिए जा सकते हैं, साथ ही वे शर्तें जिन पर सटे हुए क्षेत्रों के पट्टों का समामेलन किया जा सकता है, और पट्टादार द्वारा देय अधिकतम और न्यूनतम किराए का निर्धारण, चाहे खान में काम किया जा रहा हो या नहीं। धारा 6 खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए नियम बनाने का प्रावधान करती है; यह उन तरीकों का निर्धारण करती है जिनसे किसी खनिज या ऐसे किसी क्षेत्र का विकास किया जा सकता है जहाँ खनन पट्टा देने पर प्रतिबंध है, और इंजनों, मशीनरी या अन्य उपकरणों के उपयोग को निर्धारित या विनियमित करके किसी भी क्षेत्र में खनिज संसाधनों के विकास आदि का प्रावधान करती है। खनन क्षेत्रों और खनिजों के संरक्षण, विकास और विनियमन के ये प्रावधान कमोबेश पूरी तरह से विफल हो जाएंगे यदि 'खनन पट्टा' शब्द की परिभाषा में खनन उप-पट्टा शामिल नहीं होता; क्योंकि तब कानून से बचने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति

के लिए केवल इतना ही आवश्यक होता कि वह अपने और मालिक के बीच एक मध्यस्थ खड़ा कर दे और उससे एक उप-पट्टा प्राप्त कर ले, जो अधिनियम और नियमों के नियामक नियंत्रण से मुक्त होता। अतः हमारा यह मत है कि धारा 3(डी) के स्पष्ट शब्दों और उस उद्देश्य तथा प्रयोजन को देखते हुए जिसके लिए अधिनियम पारित किया गया था, यह स्पष्ट है कि 'खनन पट्टा' शब्द की परिभाषा के भीतर खनन उप-पट्टा शामिल है और अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके विरुद्ध हो। इसलिए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया कोई भी खनन उप-पट्टा, धारा 3(डी) में परिभाषित 'खनन पट्टा' शब्द के अंतर्गत आता है और वह अधिनियम तथा नियमों के अधीन है।

बिंदु (ii) के संबंध में।

इस संबंध में तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 4 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अलावा किसी अन्य तरीके से कोई खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा और अन्यथा दिया गया कोई भी खनन पट्टा शून्य और प्रभावहीन होगा। धारा 5 और 6 केंद्र सरकार को ऊपर बताए गए उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति देती हैं और धारा 4 के तहत दिए गए खनन पट्टों का उल्लेख करती हैं। इसके बाद धारा 7 आती है, जो यह निर्धारित करती है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए किसी भी खनन पट्टे के नियमों और शर्तों को संशोधित करने या बदलने के उद्देश्य से नियम बना सकती है, ताकि ऐसे पट्टे को धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाया जा सके। यह तर्क दिया गया है कि जहाँ अधिनियम और नियमों के लागू होने से पहले एक खनन पट्टा दिया गया है, वहाँ केवल धारा 7 के तहत बनाए गए नियम ही ऐसे पट्टादार द्वारा दिए गए किसी भी उप-पट्टे को प्रभावित करेंगे, भले ही वह उप-पट्टा उस तारीख के बाद दिया गया हो जब अधिनियम और नियम लागू हो चुके थे। हमारी राय में, धारा 7 पूरी

तरह से एक अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जैसा कि उसकी उप-धारा (2) से स्पष्ट होगा। हालाँकि, इस मामले में और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जब यह मान लिया गया कि 'खनन पट्टा' शब्द में उप-पट्टा शामिल है, तो धारा 5 और 6 के तहत बनाए गए नियम ऐसे उप-पट्टे पर लागू होंगे, यदि वह अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया है। वर्तमान मामले में, उप-पट्टा उस क्षेत्र में अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया था जिससे वह उप-पट्टा संबंधित है, और इसलिए वह उप-पट्टा अधिनियम और नियमों द्वारा शासित होगा। इस मामले में अधिनियम के प्रारंभ से पहले दिए गए किसी भी खनन पट्टे के नियमों और शर्तों को संशोधित या परिवर्तित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अधिनियम और नियम एक ऐसे उप-पट्टे के संबंध में लागू किए जा रहे हैं जो धारा 3(डी) में दी गई परिभाषा के अनुसार एक खनन पट्टा है और जिसे अधिनियम और नियमों के लागू होने के बाद दिया गया है। अपीलकर्ता को दिए गए खनन पट्टे के नियमों और शर्तों में इन नियमों द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है; यहाँ केवल इतना हुआ है कि अपीलकर्ता के निदेशकों और सचिव पर अधिनियम के लागू होने के बाद, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध उप-पट्टा (जो कि एक खनन पट्टा है) देने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। अतः अपीलकर्ता के इस तर्क में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

इस अपील में कोई सार नहीं है और इसे सव्यय खारिज किया जाता है। केवल एक पक्ष की सुनवाई की लागत दी जाएगी।

अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।